साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 14 • कठुआ, शनिवार 4 अप्रैल 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

जम्मू-कश्मीर की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहरें सभी के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी : एलजी सिन्हा

सबका जम्मू कश्मीर

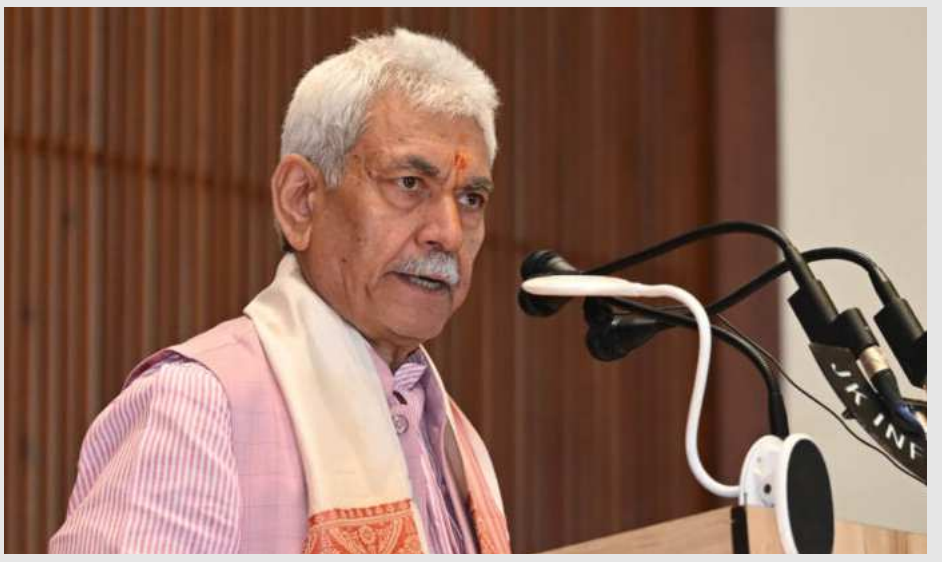

जम्म : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि जम्मू–कश्मीर की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहरें सभी के उज्ज्वल भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उपराज्यपाल ने कहा, "जम्मू की धरती समृद्ध परंपराओं से भरी है। जीवन के मूल्यों को पिरोने वाले डोगरी गीत, अनुभवों को समेटे शिल्प, भक्ति से ओतप्रोत कला हमारी जीवंत विरासतें हैं जो नई जान फूंक रही हैं।" उपराज्यपाल

जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित "जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव" के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित जुनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज भी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, लोक कलाओं, आध्यात्मिक आधारों और परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना और हमारी पहचान को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि पारंपरिक प्रस्तुतियां वातावरण को रंग और मधुरता से जीवंत कर देंगी, सांस्कृतिक प्रदर्शन हमारी अमूल्य विरासत को सभी तक पहुंचाएंगे और किसान जागरूकता कार्यक्रम इस केंद्र शासित प्रदेश की आत्मा को पोषित करने वाले हाथों का सम्मान करेंगे।"

उपराज्यपाल ने कहा कि उभरते भारत का कर्तव्य है कि वह अपनी ज्ञान अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए और नवाचारों, सांस्कृतिक मूल्यों और दार्शनिक विच. ारों का वैश्विक स्तर पर प्रसार करे। उन्होंने कहा , "इस निर्णायक क्षण में जब वैश्विक संघर्ष समा. जों को विभाजित कर रहा है और मानवता शांति की तलाश में है, भारत विश्व के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने हजारों साल पहले महाद्वीपों में ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता के दीपक प्रज्वलित किए थे।"

उपराज्यपाल ने कहा कि विश्व नए विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है और युवा पीढ़ी परिवर्तनकारी सोच को जन्म देने वाली परंपरा को आगे बढ़ा

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने आग और अन्य आपदा पीड़ितों की राहत के लिए 50 लाख रूपये के सीडीएफ (कंजर्वेटिव फंड) के इस्तेमाल को मंजूरी दी : मुख्यमंत्री उमर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2026–27 में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सीडीएफ) से ऐसे परिवारों को मकानों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता प्रदान कर सकेंगे।

विधानसभा में यह जानकारी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी गई, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शमीम फिरदौस ने प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सीडीएफ के दिशा–निर्देशों में संशोधन कर सहायता के दायरे को व्यापक बनाया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को

■ शेष पेज 2...

श्रेय सिंहल ने सूचना निदेशक का पदभार संभाला

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में आईएएस अधिकारी श्रेय सिंहल ने आज सूचना निदेशक, जम्मू–कश्मीर का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की, जिसमें विभाग के कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उन्होंने सूचना के पारदर्शी, समयबद्ध और जनकेंद्रित प्रसार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग सरकार और आम नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी स्पष्ट, सटीक और समय पर हो। इससे न केवल सरकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में प्रभावी संचार व्यवस्था किसी भी प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों

■ शेष पेज 2...

कश्मीर में यूएपीए मामले में सीआईके ने आरोपपत्र दाखिल किया, समन्वित सोशल मीडिया दुष्प्रचार नेटवर्क का पर्दाफाश किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने बुधवार को श्रीनगर में एनआईए की एक विशेष अदालत में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके मनगढ़ंत बातें फैलाने, अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने और क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

एक बयान में, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने आज, 1 अप्रैल 2026 को, श्रीनगर स्थित एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश की माननीय अदालत के समक्ष निम्नलिखित आरोपियों, डॉ. उमर फारूक भट, पुत्र फारूक अहमद भट, निवासी बुगम, कुलगाम और शहजादा अख्तर, पत्नी डॉ. उमर फारूक भट, निवासी बुगम, कुलगाम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 62(2) और गैरकानूनी गति. विधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए(पी) अधिनियम) की धारा 13, 38, 39 के तहत पुलिस स्टेशन सीआईके श्रीनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2025 के संबंध में एक आरोप पत्र (चालान) प्रस्तुत किया है।

विश्वसनीय और पुख्ता जानक. ारी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि आरोपी शाहजादा अख्तर ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन दुख्तरान–ए–मिल्लत के सदस्यों के साथ सुनियोजित आपराधिक साजिश रचकर और अपने पति डॉ. उमर फारूक

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

जम्मू-कश्मीर की...

रही है। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों की ओर लौटने, नए विच. ारों और नवाचारों को विकसित करने और सांस्कृतिक विरासत को समाज के परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया।

"इस परस्पर जुड़े युग में, भाईचारे के बंधन को मजबूत करें। विश्व स्तर पर संघर्ष की जगह करुणा को बढ़ावा दें," उपराज्यपाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा। उपराज्यपाल

ने कहा कि कला और संस्कृति में गहन अंतर्दृष्टि, उद्देश्य और शिल्प कौशल निहित हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कला, आध्यात्मिकता, दर्शन और नैतिकता पीढ़ियों को जोड़ने वाले सेतु हैं।

उपराज्यपाल ने कहा, "यह आधुनिक इतिहास का सबसे कठिन दौर है, और हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रगति और कल्याण के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं।"

उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 12 वर्षों में भारत का परिवर्तन असाधारण रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज को सामूहिक रूप से इस परिवर्तन को गति देनी चाहिए। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि आने वाले दशकों में, हमें घरेलू और वैश्विक उद्योगों को नया रूप देने वाली प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के निर्माण के लिए नई ऊर्जा और संकल्प का उपयोग करना होगा। उन्होंने

कहा, "अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, भारत ने प्राचीन गौरव और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लिया है। भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्योगपति और नवप्रवर्तक अब वैश्विक चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं; उनकी प्रौद्योगिकियां और प्रतिभाएं विश्व स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर रही हैं। मैं इसे एक पुनर्जागरण के रूप में देखता हूं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित कर रहा है।"

जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शनी, पारंपरिक लोक प्रदर्शन, किसान मेला और निःशुल्क चिकित्सा शिविर सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं।

इस अवसर पर, अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।

विधानसभा सदस्य शाम लाल शर्मा और देवयानी राणा; श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री; श्री मुकुल कानिटकर, प्रमुख नागरिक और बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए।

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य सुरेश कुमार शर्मा भी उपस्थित थे। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर सरकार...

इसका लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब विधायक वित्त वर्ष 2026-27 में आपदा प्रभावित परिवारों को आवास सहायता के रूप में अधिकतम 50 लाख रुपये तक की राशि आवंटित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की आपदा से प्रभावित सभी परिवार इसके अंतर्गत सहायता पाने के पात्र होंगे। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके घर प्राकृतिक या आकस्मिक घटनाओं में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

संशोधित दिशा-निर्देशों में 'आपदा' शब्द की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत आग लगने जैसी घटनाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपदा से प्रभावित व्यक्ति को राहत पाने में अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

श्रीनगर जिले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हब्बा कदल क्षेत्र से संबंधित 24 मामलों में अग्नि पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन मामलों की अनुमानित लागत 12.80 लाख रुपये आंकी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि इनमें से पांच मामलों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अतिरिक्त सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

शेष 19 मामलों पर फिलहाल श्रीनगर के उपायुक्त स्तर पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिन मामलों की अनुशंसा संबंधित विधायक द्वारा की गई है, उन पर नियमों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय को आम लोगों के हित में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे आपदा के समय प्रभावित परिवारों को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल सकेगी।

श्रेय सिंहल ने...

की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में सूचना विभाग की भूमिका बेहद अहम है। इस दिशा में विभाग को और अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बनना होगा।

सूचना निदेशक ने विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग कर संचार प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि बदलते समय के साथ संचार के तरीकों में भी बदलाव जरूरी है और विभाग को नई तकनीकों को अपनाकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी चाहिए। इससे सूचना का प्रसार अधिक प्रभावी और व्यापक स्तर पर किया जा सकेगा।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना मुख्यालय डॉ. ज़हूर अहमद रैना, संयुक्त निदेशक सूचना जम्मू दीपक दुबे, उप निदेशक सूचना जनसंपर्क एवं दृश्य-श्रव्य जाविद अहमद राथर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने नई निदेशक का स्वागत किया और विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग का आश्वासन दिया।

कश्मीर में यूएपीए...

भट की सक्रिय मिलीभगत से कश्मीर की स्थिति के बारे में झूठे, मनगढ़ंत और विकृत बयान गढ़ने और फैलाने में संलिप्त थी।

जांच में पता चला कि आरोपी, प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर, तथ्यों में हेरफेर करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे थे।

उनके द्वारा प्रसारित सामग्री का उद्देश्य अलगाववादी और पृथकतावादी भावनाओं को बढ़ावा देना था, जिससे भारत संघ के प्रति असंतोष, घृणा और शत्रुता को बढ़ावा मिले।

बॉर्डर रोड की बदहाल हालत उजागर : 6-7 साल बाद भी मरम्मत नहीं, गड्ढों में "लेपापोती" कर विभाग ने झाड़ा पल्ला

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन/कोटपुनु : बॉर्डर रोड की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है। मढ़ीन, कोटपुनु से हरियाचाक तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस सड़क पर करीब 6-7 साल पहले आखिरी बार तारकोल डाली गई थी, लेकिन उसके बाद कोई ठोस मरम्मत नहीं की गई। नतीजतन सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है और हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है।

बीते दो दिनों से बीआरओ द्वारा सड़क के गड्ढों को भरने के लिए तारकोल डाली जा रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि यह काम सिर्फ "लेपापोती" तक सीमित है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गड्ढों को ठीक करने के बजाय ऊपर-ऊपर से भरने का काम किया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग को सड़क की स्थिति के बारे में बताया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में डाली गई तारकोल भी पहली ही बारिश में उखड़ गई, जिससे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

पूर्व सरपंच सोमराज, नरेश कुमार, कुलद. ीप राज, महेंद्र पाल और खेमराज सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की पूरी तरह से नई और टिकाऊ मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और हादसों पर रोक लग सके।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों पर गठित समिति जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी, उन्होंने कार्यान्वयन का आश्वासन दिया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों और आकस्मिक कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में प्रमुखता से उठा, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार की स्पष्ट और दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए गठित विशेष समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात उस समय कही जब उन्होंने विधानसभा में एम.वाई. तारिगामी द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक में विभिन्न सरकारी विभागों में दशकों से कार्यरत दिहाड़ी और आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का विरोध विधेयक की भावना के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके पेश किए जाने के समय और प्रक्रिया को लेकर है।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक सहमति है और सभी पक्ष यह मानते हैं कि वर्षों से सेवा कर रहे श्रमिकों को नियमित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है और इस वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने इस सत्र के दौरान कई बार यह आश्वासन दिया है कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वादों से पीछे हटती या लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाती, तो ऐसे विधेयक को स्वीकार करने की आवश्यकता होती, लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार पहले से ही इस दिशा में सक्रिय है।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार पहले ही दिन इस विधेयक को स्वीकार कर लेती है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार ने

अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट भाषण, उपराज्यपाल के संबो.धन और सदन में दिए गए विभिन्न उत्तरों में सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और वह उस पर कायम है।

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष 19 मार्च को की गई घोषणा का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन की बात कही थी। इस समिति को दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाना था।

उन्होंने कहा कि यह समिति अपने कार्य के अंतिम चरण में है और जल्द ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वा.सन दिया कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार उसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि श्रमिकों को उनका अधिकार मिल सके।

जम्मू–कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हजारों मजदूर ऐसे हैं, जो पिछले दो से तीन दशकों से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक उनकी सेवाएं नियमित नहीं हो पाई हैं। इन मजदूरों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकारी कार्यों में लगाए हैं और अब वे स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन श्रमिकों की भावनाओं को समझती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में लगाया है, उन्हें किसी न किसी रूप में नियमित किया जाए, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे श्रमिकों को सम्मान और स्थिरता प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में लिए जाने वाले सभी निर्णय पारदर्शी और न्यायसंगत होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक की अवधि में सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेगी।

अंत में उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि सरकार अपने वादों पर कायम रहेगी और दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के मुद्दे को जल्द ही समाधान तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशें आते ही उन्हें लागू किया जाएगा, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे श्रमिकों को राहत मिल सके और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो सकें।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जिन्होंने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दक्षिणी कमान का नेतृत्व किया था, ने बुधवार को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।

यह सम्मानित सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लेंगे।

साउथ ब्लॉक के लॉन में आयोजित एक समारोह में, जनरल अधिकारी ने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण नेतृत्व पद ग्रहण करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

एक दिन पहले, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ के रूप में अपने पूर्व पद से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दक्षिणी कमान युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

अधिकारियों ने बताया कि पुणे स्थित कमान के सभी रैंकों को दिए अपने संदेश में, जनरल अधिक.ारी ने उनसे प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके, बहु–क्षेत्रीय अभियानों के लिए युद्धक क्षमताओं को परिष्कृत करके और भविष्य के लिए तैयार बल की नींव को मजबूत करके अपनी परिचालन बढ़त को बनाए रखने का आग्रह किया। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने 1 जुलाई, 2024 से इस वर्ष 31 मार्च तक विशिष्ट दक्षिणी कमान के 51वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ के रूप में कार्य किया।

जब भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर निर्णायक सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तब लेफ्टिनेंट जनरल सेठ दक्षिणी कमान के प्रमुख थे। नौसेना और वायु सेना के दो अन्य शीर्ष अधिक.ारियों के साथ, उन्होंने पिछले साल नवंबर में गुजरात के पोरबंदर तट पर आयोजित महत्वपूर्ण त्रि–सेवा अभ्यास, ष्त्रिशूलष् को भी देखा था।

खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को 20 दिसंबर, 1986 को द्वितीय लांसर्स में कमीशन प्राप्त हुआ था।

इस जनरल ऑफिसर ने स्किनर्स हॉर्स, 98 आर्मर्ड ब्रिगेड, काउंटर इंसर्जेंसी यूनिफॉर्म फोर्स, 21 कोर और दिल्ली क्षेत्र की कमान संभाली है।

वह एनडीए में प्रशिक्षक और सहायक एडजुटेंट और अहमदनगर स्थित आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल के स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में मुख्य प्रशिक्षक रह चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने 1995–96 में संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन (यूएनएवीईएम–प्प्प्) में ऑपरेशन अधिकारी के रूप में कार्य किया था।

जनरल ऑफिसर ने 1 नवंबर, 2023 से 30 जून, 2024 तक दक्षिण पश्चिमी कमान की कमान संभाली। रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था, ष्जनरल ऑफिसर द्वारा नियुक्त स्टाफ पदों में एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, सैन्य सचिव शाखा में सहायक सैन्य सचिव, मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (संच.ालन), परिप्रेक्ष्य योजना (योजना) के उप महानिद.ेशक और हथियार और उपकरण के अतिरिक्त महा.निदेशक शामिल हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स में ष्सिल्वर सेंचुरियनष् पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने रेडियो इंस्ट्रक्टर कोर्स और जूनियर कमांड कोर्स दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

BFCI OF EDUCATIONAL & TECHNIOLOGY

BRIGHT FUTURE COMPUTER INSTITUTE OF EDUCATIONAL AND TECHNOLOGY

Mr. Jatinder Khajuria (M.D)

UNDER THE MANAGEMENT OF SAHYOG INDIA EDUCATIONAL & WELFARE TRUST (Regd.)

SPECIAL OFFER: GET ONE MONTH ABSOLUTELY FREE ON A 3-MONTH BASIC COMPUTER COURSE. THIS OFFER IS AVAILABLE FOR A LIMITED TIME ONLY.

COURSE:- DIPLOMA IN COMPUTER SOFTWARE 1 YEAR '
CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION (CCA)'
CERTIFICATE IN COMPUTER BASIC (CCB) ' KIDS COURSE "
CERTIFICATE COURSE IN COMPUTER HARDWARE (C.C.?.)

Address : Ward No. 2, Opp. Distt. Court, Kathua
Mob: 99062-18160, 94191-99642
e.mail: brightfuture327@rediff.com
website: www.jatinder 327.perperonity.com

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

समय की मांग : शांति, सह–अस्तित्व और मानवता आधारित विश्व व्यवस्था की आवश्यकता

आई. डी. खजूरिया

आज का दौर मानव इतिहास के सबसे निर्णायक समयों में से एक है। विज्ञान, तकनीक और विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद, दुनिया अनेक गंभीर संकटों का सामना कर रही है। एक ओर जहां मानव ने अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना ली है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर शांति, स्थिरता और संतुलन लगातार खतरे में हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि हम वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से विश्लेषण करें और भविष्य के लिए एक नई दिशा निर्धारित करें।

आज विश्व के सामने सबसे बड़ा खतरा युद्धोन्मादी सोच और सत्ता व धन के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। कुछ शक्तिशाली कॉरपोरेट और राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसी नीतियां अपना रहे हैं, जो पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी लालच और शक्ति का दुरुपयोग हुआ है, तब मानवता को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हिरोशिमा और नागा. साकी जैसी त्रासदियां आज भी हमें यह चेतावनी देती हैं कि यदि समय रहते हमने अपनी सोच नहीं बदली, तो ऐसे हादसे फिर दोहराए जा सकते हैं।

वर्तमान समय में विश्व के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर पश्चिम एशिया, ईरान, इज़राइल और आसपास के क्षेत्रों में जारी तनाव ने वैश्विक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन संघर्षों का प्रभाव केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है। क्योंकि आज का विश्व पूरी तरह परस्पर निर्भर है, इसलिए किसी एक क्षेत्र का संकट वैश्विक संकट में बदल सकता है।

इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी मानव अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वनों की कटाई, प्रदूषण और असंतुलित विकास मॉडल ने पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंचाई है।

यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि विकास के साथ–साथ प्रकृति के संरक्षण को भी समान महत्व दिया जाए।

इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक नई और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। आज आवश्यकता है "शांति और परस्पर निर्भरता की राजनीति" को अपनाने की। इस नई सोच में सहिष्णुता, सह–अस्तित्व, विविधताओं का सम्मान और सभी समुदायों, जातियों, भाषाओं और राष्ट्रों के प्रति समान दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। दुनिया के हर देश को यह समझना होगा कि स्थायी विकास और शांति केवल सहयोग और संवाद से ही संभव है, न कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से।

विश्व व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत बनाने के लिए संघीय ढांचे की अवधारणा पर भी विचार किया जाना चाहिए। "एक राष्ट्र, एक वोट" का सिद्धांत वैश्विक स्तर पर समानता को बढ़ावा दे सकता है।

इसके साथ ही, वीटो पावर जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि यह कुछ देशों को असमान रूप से अधिक शक्ति प्रदान करती है और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक विवादों का समाधान केवल शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए।

युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि यह नई समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए संवाद, कूटनीति और समझौते के माध्यम से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा, परमाणु हथियारों और अन्य विनाशकारी हथियारों का पूर्ण उन्मूलन भी समय की मांग है। हथियार निर्माण उद्योग न केवल संसाधनों की बर्बादी करता है, बल्कि यह विश्व शांति के लिए भी खतरा बना रहता है।

विकास के वर्तमान मॉडल में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज का विकास अक्सर असमानता को बढ़ावा देता है, जहां एक ओर कुछ लोग अत्यधिक संपन्न हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी आबादी गरीबी और अभाव में जीवन जीती है। इसलिए एक ऐसा मॉडल अपनाना जरूरी है, जो समानता, न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित हो। अमीर और गरीब के बीच की खाई को सीमित करना भी सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है।

अंततः, यह समझना जरूरी है कि पृथ्वी केवल वर्तमान पीढ़ी की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। यदि हम आज अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए यह समय है कि हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए प्रयास करें, जो शांति, सह–अस्तित्व और मानवता के मूल्यों पर आधारित हो।

यही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

– आई. डी. खजूरिया

"महिला सुरक्षा के दावे फेल : गाजियाबाद के नंदग्राम में 'पिंक बूथ' पर लटका ताला"

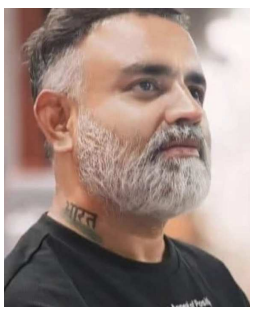

रविंद्र आर्य

'महिला सुरक्षा का ढोंग या जमीनी सच्चाई? नंदग्राम की रिपोर्ट ने खोली पोल'

गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र से महिला सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीरे बार बार सामने आई है, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'पिंक बूथ' जैसी योजनाओं पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है।

न्यूज इंडिया 1 की हालिया रिपोर्ट (रिपोर्टररू जितेंद्र गौतम) द्वारा खुलासा हुआ है कि नंदग्राम क्षेत्र में स्थित पिंक बूथ पर ताला लटका हुआ है। इतना ही नहीं, वहां शिकायत दर्ज कराने के लिए जो संपर्क नंबर दिया गया है, वह भी अमान्य पाया गया।

पिंक बूथ : कागजों में सक्रिय, जमीन पर बंद

पिंक बूथ का उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और उन्हें सुरक्षित माहौल देना है। लेकिन जब वही बूथ बंद मिले और संपर्क के साधन निष्क्रिय हों, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं?

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस मुद्दे पर जब पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो क्ब्ब सिटी धवल जायसवाल का फोन तक नहीं उठाया गया। इससे प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े होते हैं।

'राखी पहलवान का आरोप : "न्याय मांगने पर अपमान मिला"'

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राखी पहलवान का बयान भी सामने आया है, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

राखी पहलवान के अनुसार, वह एक 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में समर्थन देने और न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचीं थीं। लेकिन वहां उन्हें समर्थन मिलने के बजाय कथित रूप से अपमान का सामना करना पड़ा।

उनका आरोप है कि नंदग्राम क्षेत्र के एसीपी ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल से कहकर उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकालने का निर्देश दिया।

राखी पहलवान ने इसे लोकतंत्र में महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया और कहा कि आज यदि कोई महिला पीड़िता के लिए आवाज उठाती है, तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है।

बड़ा सवालरू क्या यही है महिला सुरक्षा का मॉडल?

इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैंरू

क्या महिला सुरक्षा केवल सरकारी घोषणाओं तक सीमित है?

क्या पिंक बूथ जैसी योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं?

क्या पुलिस तंत्र महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है?

रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि जब शहर के बीचों–बीच यह हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कितनी बदतर हो सकती है।

सिस्टम पर भरोसा या सवाल?

नंदग्राम की यह घटना कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की गंभीर विफलता का संकेत देती है। एक ओर जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और मौत जैसी संवेदनशील घटना सामने आती है, वहीं दूसरी ओर महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए तंत्र का निष्क्रिय होना और आवाज उठाने वालों के साथ दुर्व्यवहारकृयह स्थिति बेहद चिंता. जनक है। यदि न्यूज इंडिया 1 की यह रिपोर्ट सामने न आती, तो शायद यह सच्चाई भी छिपी रह जाती।

अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ दब जाएगा?

राजनैतिक व्यंग्य–समागम'

रूपये का ख़त, भारत के नाम -- मुझे डॉलर के नहीं, चुनाव आयोग के मुक़ाबले देखो

रवीश कुमार'

प्रिय भारत,

मैं रुपया हूं। मैं ठीक हूं। थोड़ी हरारत–सी हो जाती है। बुख़ार तो चढ़ता जा रहा है, लेकिन कमज़ोरी नहीं है। एक डॉलर जब भी सामने आता है, मेरी कंपकंपी बढ़ जाती है। और कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने डोलो ले लिया है। डोलो लेने के बाद डॉलर के सामने थोड़ा तन जाता हूं, डोलो का असर कम होता है, थोड़ा लचक जाता हूं।

कभी नहीं सोचा था कि एक डॉलर के सामने मेरा मोल 95 तक चला जाएगा। मैं कमज़ोर कहा जाऊंगा। मेरी कमज़ोरी के नाम पर एक मज़बूत सरकार आई, जो हर दिन मज़बूत होती चली गई और मैं कमज़ोर होता गया।

तब तो मैं एक डॉलर के सामने 62 रुपया था, आज 95 हो गया हूं। मेरी कमज़ोरी की आप चिंता मत कीजिए। मैं रुपया हूं। इसमें मेरा दोष नहीं है। दोष आप लोगों का है। आप डॉलर कमा नहीं सके, आप डॉलर बचा नहीं सके, आप डॉलर फंसा नहीं सके।

जितना डॉलर आता है, उतना बाहर चला जाता है। डॉलर को जाने से नहीं रोक पाने वाली सरकार के कारण मैं कमज़ोर हो जाता हूं। विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर गए हैं, आपका नहीं लेकर गए। जब भी अपना पैसा लेकर जाते हैं, मुझे कमज़ोर कर जाते हैं।

मेरी कमज़ोरी की आप चिंता न करें। मेरी कमज़ोरी दूर करने के नाम पर मज़बूत होने वाली सरकार की चिंता करें।

यह सरकार इतनी मज़बूत हो गई कि 2016 में मुझे रातों–रात बंद कर दिया गया। नोटबंदी हो गई। मुझे डॉलर से डर नहीं लगता है। मुझे 8 पीएम से डर लगता है। कब आठ बजते ही पीएम मुझे बंद कर दें। नोटबंदी के समय सपना दिखाया कि बिस्तरों में, दीवारों में जो काला धन गड़ा है, बाहर आ जाएगा। आया तो नहीं, मैं जब नोटबंदी के बाद बाहर आया तो खोया–खोया सा रहने लगा। सारे चंदे एक ही दिशा में जा रहे थे मैं सहमा–सहमा यह सब देखता रहा और डॉलर के सामने कभी लजाते हुए 92 होता रहा, तो कभी शर्माते हुए 95 होता रहा।

वित्त मंत्री मेरी डॉक्टर हैं। रिज़र्व बैंक के गवर्नर मेरे कार्डियो डॉक्टर हैं। जैसे ही मेरा कॉलेस्ट्रोल बढ़ता है, वो मार्केट में डॉलर को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। इस कमज़ोरी में भी मैं वोटर के खाते में पहुंचकर रिज़ल्ट निकाल देता हूं।

इस चुनाव में भी मैं 30,000 करोड़ बंटने वाला हूं। बस इतना ही बदला है। मुझे बांटकर वोट मिल जाता है। आप मुझे हमेशा डॉलर के मुकाबले मत देखो। देखना है तो मुझे चुनाव आयोग के मुकाबले देखो, लाभार्थी योजना के मुकाबले देखो, वोटर के मुकाबले देखो। मैं नहीं, मुझे पाकर वोट देने वाले लोग कमज़ोर हुए हैं। मैं ठीक हूं। अपनी चिंता करो, मेरी नहीं।

तुम्हारा,
'रुपया'

'(पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका तथा रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं।)'

एक बार फिर पॉपा वॉर रूकवा देंगे!

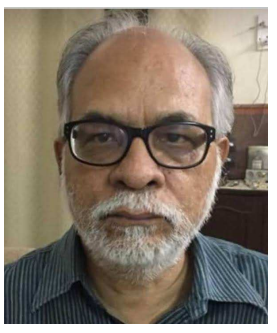

राजेंद्र शर्मा'

भागवत जी ने एकदम सही कहा — भारत ही यह युद्ध रुकवा सकता है। यह युद्ध यानी ईरान और अमरीका–इस्राइल के बीच का युद्घ। वैसे भागवत जी ने भी विनम्रता से काम लिया और बाकी सारी दुनिया पर मोदी से युद्ध रुकवाने की मांग करने की जिम्मेदारी डाल दी। बोल दिया कि सारी दुनिया ऐसा कह रही है। वैसे भागवत जी का बड़प्पन है कि उन्होंने दुनिया के कहने को इतना महत्व दिया। वर्ना वह तो सीधे भी मोदी जी को युद्ध रुकवाने के लिए कह सकते थे, उनसे युद्ध रुकवाने की मांग कर सकते थे। मांग कर सकते थे, माने मोदी जी को परामर्श दे सकते थे। और परामर्श भी मोदी जी के घर जाकर, भोजन के उपरांत दे सकते थे, एकांत में। या मोदी जी को अपने घर नागपुर बुलाकर भी परामर्श दे सकते थे। पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह परामर्श दिया, बल्कि अपेक्षा जताई — मोदी जी ही यह युद्ध रुकवा सकते हैं।

वैसे भागवत जी की दूरदर्शिता भी माननी पड़ेगी। मोदी से युद्ध रुकवाने के लिए कहा जरूर, पर तुरंत रुकवाने के लिए नहीं कहा। तुरंत की छोड़िए, कोई टाइमलाइन दी ही नहीं। मोदी जी पर है, अपनी सहूलियत से कभी भी युद्ध रुकवा दें। बस युद्ध रुकवा दें। यूक्रेन–रूस युद्ध के टैम पर, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए युद्ध रुकवाने के लिए मोदी जी पर, इन छात्रों के माता–पिता ने जिस तरह का दबाव डाला था, वैसा दबाव डालने की गलती भागवत जी ने बिल्कुल नहीं की। बेशक, मोदी जी ने तुरंत रुकवाओ, अभी रुकवाओ के ध्यान बंटाने वाले शोर के बावजूद, वॉर तब भी रुकवायी थी। बल्कि देश के विद.श मंत्रालय तक को बताए बिना वॉर रुकवायी थी, तभी बेचारा विदेश मंत्रालय तो बाद तक इससे इंकार ही करता रह गया कि मोदी जी ने वॉर रुकवायी थी। लगता है कि मोदी जी ने बस देश के रक्षा मंत्री को बताया था कि वह वॉर रुकवा रहे हैं और उन्हीं ने बाद में देश को बताया कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी थी। यह दूसरी बात है कि, "वॉर रुकवा दी पॉपॉ" वाली हीरोइन का वीडियो, उससे पहले ही सारी दुनिया को खबर दे चुका था — "मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पॉपॉ"!

वैसे भागवत जी का मोदी जी को वॉर रुकवाने का सार्वजनिक रूप से परामर्श देना भी एक तरह का मास्टर स्ट्रोक ही हुआ। सिर्फ मोदी जी के वॉर रुकवाने से वह संदेश शायद नहीं जाता, जो भागवत जी के कहने पर मोदी जी के वॉर रुकवाने से जाएगा। इस संदेश से आरएसएस को हिंदूवादी कम और मुस्लिम–विरोधी, ईसाई–विरोधी और कम्युनिस्ट–विरोधी ज्यादा मानने वालों के मुंह तो एकदम सिल ही जाएंगे। सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आरएसएस का स्वयंसेवक, अपने सरसंघचालक के परामर्श से वॉर रुकवा रहा होगा। और वॉर भी ऐसी, जिसका हिंदुओं से कुछ लेना–देना ही नहीं है, सिवाय रसोई गैस और तेल के दाम के। मुसलमान ईरान पर, ईसाई अमरीका और यहूदी इस्राइल का हमला! अगर भगवत–मोदी का हिंदुत्व इन दोनों के खिलाफ होता, तो भागवत जी मोदी जी को वॉर रुकवाने के लिए कहते क्या? युद्घ को, जब तक चलता, चलने नहीं देते क्या? बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के मुसलमान क्या अब भी यह बात नहीं समझेंगे कि जो मोदी जी मुसलमानों और ईसाइयों–यहूदियों के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं, उनके खिलाफ हिंदुत्ववादी युद्ध रुकवाने के लिए कितने जरूरी हैं।

और सौ बातों की एक बात, यूक्रेन युद्ध में यह साबित हो चुका है कि वॉर तो पॉपॉ ही रुकवाएंगे! हमारे भक्तों के पास पॉपॉ हैं — मोदी जी। सो वॉर तो मोदी जी ही रुकवाएंगे। बस एक ही डर था। कहीं अगले शांति के नोबेल के चक्कर में ट्रंपवा, "ऑपरेशन सिंदूर" की तरह, यह वॉर रुकवाने का भी दावा करने नहीं आ जाए। पर ये पाकिस्तान वॉर रुकवाने कहां से आ गया! ट्रंप जी आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। वॉर रुकवाने का काम तो पॉपॉ का है, इसका ताज किसी भी ऐरे–गैरे के सिर पर कैसे रखे दे रहे हैं।

'(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका श्लोकलहरश के संपादक हैं।)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

पश्चिम एशिया युद्ध : मोदी ने कहा कि भारत ने स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला; कांग्रेस की तुलना राजनीतिक गिद्धों से की

सबका जम्मू कश्मीर

थारद (गुजरात) : नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध, अशांति और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारत ने अपनी सशक्त विदेश नीति और देशवासियों की एकता के बल पर स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है। उन्होंने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

गुजरात के वाव–थारद क्षेत्र के नानी गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और ईंधन की कीमतों में भी उछाल आया है। ऐसे कठिन समय में भारत ने संतुलन और संयम का परिचय दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति आज इतनी मजबूत है कि वह हर वैश्विक परिस्थिति में देशहित को सर्वोपरि रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देशवा. सियों की एकजुटता भी इस मजबूती का अहम आधार है, जिसके कारण भारत किसी भी संकट का डटकर सामना करने में सक्षम है। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस गंभीर स्थिति में भी देशहित के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम और भय फैलाने में लगी हुई है, ताकि लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक रूप से लंबी कतारें लगाएं और अव्यवस्था का माहौल बने। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि यह समय एकजुट होकर देश का साथ देने का है, न कि जनता को भड़काने का। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ष्राजनीतिक गिद्धोंष् की तरह स्थिति के और बिगड़ने का इंतजार करते हैं, ताकि वे उसका फायदा उठा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि का सीधा असर आम जनता पर न पड़े। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को राहत मिलती रहे और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबा. `धन में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनने की क्षमता रखता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि

जम्मू–कश्मीर के शिक्षा मंत्री इटू ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य बना रही है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मंगलवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

विधानसभा में विधायक खुर्शीद अहमद शेख के नए विषयों को शामिल करने से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता, बहुविषयक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में।

इटू ने कहा कि सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा से संबंधित घटकों को विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है, जो संस्थानों के स्तर, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, प्रशिक्षित मानव संसाधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर निर्भर करता है।

कंप्यूटर विज्ञान, सूचना अभ्यास और आईटी को अलग–अलग विषयों के रूप में उच्च माध्यमिक स्तर (11वीं से 12वीं) के पाठ्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 15 विभिन्न व्यवसायों के साथ व्यावसायिक या कौशल आधारित शिक्षा भी लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप विभाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक विषय के रूप में शामिल करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि

राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा ढांचा 2023 में वर्णित और एनईपी में परिकल्पित 21वीं सदी के कौशलों का एकीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और संशोधित पाठ्यक्रम ढांचे में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार, सहयोग, डिजिटल साक्षरता, समस्या–समाधान और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम युक्तिकरण, संशोधित शिक्षण पद्धतियों, योग्यता–आधारित मूल्यांकन और माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल–उन्मुख मॉड्यूल के एकीकरण के माध्यम से इन दक्षताओं को व्यवस्थित रूप से सभी विषयों में समाहित किया जा रहा है।

इटू ने कहा कि एनईपी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करती है और तदनुसार, डिजिटल साक्षरता और कौशल शिक्षा जैसे क्षेत्र मूलभूत स्तर से ही पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इन दक्षताओं को कक्षा अभ्यासों में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे प्रासंगिक कौशल और सीखने के परिणामों को समग्र रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्री ने कहा कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर, डिजिटल साक्षरता और कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम के भीतर समर्पित वैकल्पिक विषयों के रूप में भी पेश किया जा रहा है, इसके अलावा इन्हें विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकीकृत किया जा रहा है।

बुडगाम के वागुरा ग्राम पंचायत को सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण शासन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर में जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, बडगाम जिले की वागूरा ग्राम पंचायत ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसवीपी) 2025 श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (एमआ. `पीआर) द्वारा स्थापित यह पुरस्कार ष्सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामा. जिक रूप से सुरक्षित पंचायतष् विषय के अंतर्गत दिया गया, जिससे वागूरा देश की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों में शामिल हो गई है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें हजारों पंचायतों ने विभिन्न विषयगत श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की।

प्रतियोगिता के व्यापक स्तर और कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया को देखते हुए

वागूरा की यह उपलब्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो केवल दस्तावेजीकरण और स्व–रिपोर्टिंग से कहीं अधिक व्यापक है।

कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता एवं चुनाव विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने वागुरा ग्राम पंचायत, बुडगाम को यह सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी और इसे जम्मू–कश्मीर में जमीनी स्तर के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जमीनी स्तर पर किए गए ठोस प्रयासों को दर्शाती है और यह साबित करती है कि पीएआई 2.0 ढांचे के तहत साक्ष्य–आधारित योजना, सामुदायिक भागीदारी और डेटा–संचालित शासन किस प्रकार ग्रामीण संस्थानों को समावेशी विकास के इंजन में बदल सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण शासन सुधारों में जम्मू–कश्मीर की बढ़ती भूमिका को मजबूती मिलती है।

डार ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सचिव, आरडीडी एवं पीआर, जम्मू–कश्मीर; निदेशक, पंचायती राज, जम्मू–कश्मीर; उप सचिव; एसीपी बुडगाम; और बीडीओ बीके पोरा के प्रति आभार व्यक्त किया।

पारंपरिक पुरस्कार प्रक्रियाओं के विप. रीत, डीडीयूपीएसवीपी 2025 मूल्यांकन में पंचायती राज मंत्रालय की एक समर्पित निरीक्षण टीम शामिल थी, जिसने जमीनी आकलन के लिए वागुरा ग्राम पंचायत का दौरा किया।

पीआर मंत्रालय की टीम ने स्वास्थ्य, शिक्षा, एनआरएलएम और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित प्रमुख विभागों के कामकाज का आकलन किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत उप–स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बुनियादी ढांचे की सेवा वितरण, दवाओं की उपलब्धता और कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में समीक्षा की गई। टीम ने एनआरएलएम से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की वित्तीय गतिविधियों, बैंक संबंधों और आजीविका परिणामों के साथ–साथ एमजीएनआरईजीए कार्यस्थल की संपत्तियों और उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता का भी आकलन किया।

बीके पोरा ब्लॉक में स्थित वागुरा पंचायत, कमजोर समूहों के सामा. जिक–आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता देकर ग्रामीण शासन के एक आदर्श के रूप में उभरी है। पंचायत की सफलता का आधार इसकी सक्रिय षकिसी को पीछे न छोड़ेंष् (एलएनओबी) नीति और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है, जो लगभग 4,000 निवा. सियों की आबादी को सेवाएं प्रदान करती है।

प्रशासन ने विशेष नामांकन शिविरों का आयोजन करके वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए आईएसएसएस और एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। पंचायत में लगभग 90 प्रतिशत दिव्यांगजनों को यूडीआईडी ष्प्कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिससे कल्याणकारी सेवाओं तक उनकी निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई। साथ ही, आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित किया गया योजना गांव भर के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

संपादकीय

स्वस्थ भविष्य शिक्षा

संपादक – राज कुमार

आज का बच्चा भोजन के बारे में अपनी पहली समझ न तो घर से प्राप्त करता है, न ही विद्यालय या पुस्तकों से, बल्कि चमकदार पैकेटों, विज्ञापनों, कार्टून पात्रों और मोबाइल स्क्रीन से सीखता है। वह यह जानने से पहले कि शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, यह पहचानने लगता है कि कौन सा चिप्स या पेय "आकर्षक" है। पानी के महत्व को समझने से पहले ही वह मीठे पेय पदार्थों के चिन्ह याद कर लेता है। यह स्थिति केवल एक सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का संकेत है। आज बच्चों को संत. ुलित आहार के एक संदेश के मुकाबले कई गुना अधिक अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। अधिक नमक, चीनी और वसा से भरपूर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उनके आसपास की दुनिया पर हावी हो चुके हैं। इस असंतुलन ने भारत में कुपोषण की एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है, जहां एक ओर बच्चों में पोषण की कमी है, वहीं दूसरी ओर मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कई परिवारों में यह दोनों समस्याएं एक साथ दिखाई देती हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में कुपोषण केवल भोजन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि असंतुलित और पोषक तत्वों से रहित आहार का भी परिणाम है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार–बार चेतावनी दी है कि बच्चों पर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के प्रचार का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी पसंद, आदतें और खान–पान का व्यवहार प्रभावित होता है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे पीएम पोषण और पोषण अभियान, जिनका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं ने लाखों बच्चों तक भोजन पहुंचाया है, लेकिन केवल भोजन देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि बच्चों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि सही भोजन क्या है और उसका महत्व क्या है, तो वे आसानी से आकर्षक लेकिन हानिक. ारक विकल्पों की ओर खिंच सकते हैं। भारत इस समय एक गंभीर दोहरे दबाव का सामना कर रहा है। एक ओर बच्चों में कुपोषण की उच्च दर बनी हुई है, तो दूसरी ओर मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल भोजन उपलब्ध कराना समाधान नहीं है। समस्या की जड़ पोषण संबंधी जानकारी की कमी है। जब तक बच्चों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि भोजन उनके शरीर, दिमाग और ऊर्जा स्तर को कैसे प्रभावित करता है, तब तक वे सही विकल्प चुनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। विद्यालय इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां बच्चों की आदतें और सोच विकसित होती है। यदि यहां उन्हें सही पोषण के बारे में व्यावहारिक और रोचक तरीके से सिखाया जाए, तो यह उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक पोषण–साक्षर बच्चा केवल अंकों के लिए पोषक तत्वों के नाम नहीं याद करता, बल्कि वह यह समझता है कि कौन सा भोजन उसे लंबे समय तक ऊर्जा देता है और कौन सा केवल कुछ समय के लिए संतुष्टि देता है। नीतिगत स्तर पर भी अब इस दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा "ईट राइट स्कूल" कार्यक्रम बच्चों को भोजन के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने का प्रयास है। इसके माध्यम से बच्चों को खाद्य सुरक्षा, पोषण और सही चुनाव करने की क्षमता सिखाई जा रही है। फिर भी यह आवश्यक है कि पोषण शिक्षा को केवल औपचारिकता न बनाया जाए। इसे रोचक, व्यावहारिक और जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना होगा कि पैकेट पर लिखी जानकारी कैसे पढ़ें, विज्ञापन कैसे उनकी सोच को प्रभावित करते हैं, और पारंपरिक भोजन क्यों अधिक लाभकारी होता है। यदि यह शिक्षा सही तरीके से दी जाए, तो बच्चे स्वयं स्वस्थ विकल्प चुनने लगेंगे। आने वाले समय में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वह पोषण शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाए। केवल बच्चों को भोजन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि सही भोजन क्या है और क्यों आवश्यक है। जब बच्चे जागरूक होंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होगा। आज के समय में जब बाजार बच्चों से लगातार संवाद कर रहा है, तब विद्यालयों को भी उतनी ही प्रभावशाली भूमिका निभानी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी केवल पेट भरी नहीं, बल्कि सच में स्वस्थ और सशक्त हो सके।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, वैश्विक व्यापार चुनौतियां और भारत की रणनीति

ट्रम्प ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया एवं 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है एवं इसे प्रसंस्कृत करने के उपरांत यूरोपीय देशों को पेट्रोल एवं डीजल के रूप में निर्यात करता है।

प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पूरी दुनिया में, विशेष रूप आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखाई दी है। ट्रम्प ने "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" – अमेरिका को पुनः महान बनायें – के नारे के साथ यह राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अतः उन्होंने अमेरिका को एक बार पुनः विश्व के विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर टैरिफ लगाने का निर्णय लेते हुए, इस निर्णय को शीघ ही लागू भी कर दिया। उनका सोचना था कि उनके इस निर्णय से विभिन्न उत्पादों के निर्यातक अमेरिका में इन उत्पादों को निर्यात करने के प्रति निरुत्साहित होकर इन उत्पादों का उत्पादन अमेरिका में ही प्रारम्भ कर देंगे। इस कार्य को यदि धीमे धीमे एवं संरचित रूप से किया जाता तो सम्भव है कि पूरे विश्व में अफरा तफरी जैसा माहौल नहीं बनता। परंतु, ट्रम्प ने कुछ देशों (चीन, आदि) से विभिन्न वस्तुओं के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी एवं अन्य देशों को भी लगातार इस प्रकार की धमकी देना प्रारम्भ कर दिया।

ट्रम्प ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया एवं 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है एवं इसे प्रसंस्कृत करने के उपरांत यूरोपीय देशों को पेट्रोल एवं डीजल के रूप में निर्यात करता है। इस प्रक्रिया में ट्रम्प ने यह निष्कर्ष निकाला भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल को खरीदने से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को बल मिलता है और भारत इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग कर रहा है। इस प्रकार, भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर दिनांक 27 अगस्त 2025 से 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया गया है। इससे भारत के पूंजी (शेयर) बाजार में हाहाकर मच गया एवं विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारत से अपने निवेश को निकाल रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका में होने वाले विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगाए गए टैरिफ पर ही नहीं रुके बल्कि अपनी साम्राज्यवादी सोच को पुनः लागू करने के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से झलका दिया। प्रभुतासम्पन्न देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में लाया गया एवं उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया। दरअसल, अमरीका की नजर वेनेजुएला के कच्चे तेल के अपार भंडार पर है। जिस पर अमेरिका अपना कब्जा स्थापित करते हुए इसके उपयोग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। साथ ही, डेनमार्क के नियंत्रण में एक द्वीप, ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार की धमकियां, मेक्सिको, क्यूबा, ईरान आदि देशों को भी दी गई हैं। ट्रम्प के उक्त प्रकार के निर्णयों के चलते अब तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच आपसी सम्बंधो पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत भी अछूता नहीं रहा है एवं हाल ही के समय में भारत के अमेरिका के साथ सम्बन्धों में कुछ खटास आई है। अन्यथा, कुछ समय पूर्व तक भारत एवं अमे. रिका एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार माने जाते रहे हैं। विदेशी व्यापार के मामले में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा साझीदार रहा है। भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात के मामले में भी अमेरिका प्रथम स्थान पर हैं। श्री ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के उपरांत भारत का विद. श व्यापार कुछ हद तक विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। परंतु, भारत ने इस समस्या का हल निकालने की रणनीति पर तुरंत विचार करना प्रारम्भ किया एवं कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए। ताकि, विशेष रूप अमेरिका को होने वाले वस्त्र एवं परिधान, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्रीय पदार्थ, खिलौना उद्योग एवं चमड़ा उद्योग जैसे श्रम आधारित उद्योगों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को तुरंत ही रोका जा सके अथवा कम किया जा सके। अन्यथा, की स्थिति में भारत में बेरोजगारी की समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप खड़ी हो सकती थी। भारत ने उक्त उत्पादों के निर्यात हेतु रूस, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के रूप में नए बाजार तलाशे एवं इन देशों को उक्त उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ किया। वर्ष 2025 में भारत ने विदेशी व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों पर गहन वार्ताओं और रणनीतिक अद्यतनों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया है। वर्ष के अंत में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान एवं न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए। इसके साथ ही, अफ्रीकी देशों एवं लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी प्रारम्भिक वार्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि दर को बनाए रखने में सफलता मिली है। सितम्बर एवं अक्टोबर 2025 माह में विशेष रूप से अमे. रिका को भारत से होने वाले वस्तुओं के निर्यात पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा था। 27 जनवरी 2026 को तो भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देकर इतिहास ही बना डाला है। इस समझौते को "मदर आफ ऑल डील्स" की संज्ञा दी जा रही है। यह मुक्त व्यापार समझौता 18 वर्षों के उपरांत सम्भव हो सका है। अब तो कनाडा के राष्ट्रपति भी मार्च 2026 माह में भारत आने वाले हैं एवं कुछ क्षेत्रों में मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल सम्भावना है। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों का विश्व के अन्य देशों को सकारात्मक संदेश गया है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है। इससे, समझौता करने वाले देशों के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की सम्भावनाएं प्रबल हो रही हैं क्योंकि इन देशों में आर्थिक प्रगति के तेज होने के चलते इन देशों में खुशहाली आने की सम्भावनाएं बन रही हैं। इस दृष्टि से विभिन्न देशों का भारत के प्रति दृष्टिकोण हाल ही के समय में बदला है एवं वे अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं। भारत एक युवा देश है एवं विभिन्न उत्पादों के लिए भारत एक विशाल बाजार के रूप में विश्व के सामने उपलब्ध है। विशेष रूप से इस धरा के दक्षिणी भाग के देश तो अब भारत के वैश्विक स्तर पर इन देशों का नेतृत्व करने के लिए श्रद्धा के भाव से उम्मीद भारी नजरों से देख रहे हैं।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भारत के सामने भी कुछ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। जैसे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत का लगातार गिरते जाना। एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत 92 रुपए के स्तर को भी पार कर गई है एवं वर्ष 2025 में भारतीय रुपए का लगभग 5 से 6 प्रतिशत के बीच अवमूल्यन हुआ है। दरअसल, यह समस्या, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी (शेयर) बाजार से लगातार अपने निवेश को निकालने के चलते खड़ी हुई है। इससे अमेरिकी डॉलर का भारत से बाहर जाने का सिलसिला बढ़ गया है। इस समस्या के हल हेतु भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहा है। साथ ही, भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात को भी गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत में अमेरिकी डॉलर के आने की मात्रा में वृद्धि हो। यदि भारत को इन प्रयासों में सफलता मिलती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव कुछ कम होगा।

ट्रम्प द्वारा हाल ही के समय में लिए गए निर्णयों के चलते वैश्विक स्तर पर प्रारम्भ हुई उथल पुथल को कम करने के लिए आज विश्व के कई देश भारत की ओर ही देख रहे हैं क्योंकि भारत अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाकर इस तरह की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास कर रहा है एवं इस कार्य में भारत को कुछ सफलता प्राप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। भारत के पास युवा शक्ति की बेजोड़ उपलब्धता है, विभिन्न क्षेत्रों में इनके कौशल को विकसित कर, भारत आज पूरे विश्व को श्रमबल उपलब्ध करा सकने की क्षमता रखता है और भारतीय सनातन संस्कृति को "वसुधैव कुटुम्बकम" के भाव के साथ, पूरे विश्व में फैला सकता है ताकि विभिन्न देशों में हो रहे संघर्षों को कम अथवा समाप्त किया जा सके।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

मुख्यमंत्री उमर ने पारदर्शी भर्ती का आश्वासन दिया; कहा कि इस साल 25,000 पद भरे जाएंगे

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दबाजी से बचते हुए सभी नियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्दबाजी में की गई भर्तियां अक्सर कानूनी विवादों में फंस जाती हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है और युवाओं को नुकसान उठाना पड़ता है।

विधानसभा सत्र के दौरान वहीद–उर–रहमान पारा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के पूरक के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 25 हजार रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नियमों को दरकिनार कर जल्दबाजी में निर्णय लिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में कई बार ऐसा हुआ है जब भर्ती सूचियों को अदालतों में चुनौती दी गई, जिसके कारण पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। उन्होंने कहा कि इन कानूनी अड़चनों के चलते न केवल भर्ती में देरी होती है, बल्कि कई योग्य उम्मीदवार आयु सीमा पार कर जाते हैं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों से बचना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन कर रही है, ताकि भर्ती प्रक्रिया न केवल शीघ्र पूरी हो, बल्कि कानूनी रूप से भी मजबूत हो। उन्होंने दोहराया कि इस वर्ष कम

से कम 25 हजार पदों को भरने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू–कश्मीर के विभिन्न विभागों में इस समय 28 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें अधिकांश पद गैर–राजपत्रित श्रेणी के हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है। इन रिक्तियों को भरने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 के दौरान 7 हजार से अधिक पदों को भर्ती के लिए जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग और जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था। इनमें 959 राजपत्रित और 6 हजार 340 गैर–राजपत्रित पद शामिल हैं। सरकार इन संस्थाओं के माध्यम से पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, जो कि कुल रिक्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। इनमें 2 हजार 497 राजपत्रित और 8 हजार 88 गैर–राजपत्रित पद सीधी भर्ती के अंतर्गत आते हैं, जबकि 898 राजपत्रित और 3 हजार 601 गैर–राजपत्रित पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां सीधी भर्ती के अंतर्गत 594 राजपत्रित और 727 गैर–राजपत्रित पद खाली हैं, जबकि पदोन्नति कोटा के तहत 2 हजार 683 राजपत्रित और 3 हजार 598 गैर–राजपत्रित पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया जारी है।

इसके अलावा वित्त, उद्योग और वाणिज्य, जल शक्ति, विद्युत विकास, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा युवा सेवाएं और खेल जैसे विभागों में भी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।

सरकार इन सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने की योजना पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी और योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

विधानसभा ने जेजेएम सदन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का विस्तार दिया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : विधानसभा ने आज जल जीवन मिशन संबंधी सदन समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया।

प्रस्ताव को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया और समय सीमा बढ़ा दी गई। सदन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया था, कि यह सदन जल जीवन मिशन संबंधी सदन समिति का कार्यकाल तीन (3) महीने के लिए बढ़ाए ताकि वह अपना कार्य पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

सदन ने गौर किया कि समिति को जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की जांच के लिए समय चाहिए और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का अति. रिक्त समय दे दिया।

विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि सदन समिति ने अधिकांश कार्य पूरा कर लिया है, हालांकि, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे और समय चाहिए क्योंकि अभी 3200 जल जीवन मिशन परियोजनाओं (डब्ल्यूएसएस) की जांच बाकी है।

जितेंद्र सिंह ने डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल और यूनियन प्रतिनिधियों से मुलाकात की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को डाक कर्मचारियों और उनके विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाक. ात कर कैडर पुनर्गठन, पेंशन और सेवा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को स्थापित नीतिगत प्रावधानों और लागू नियमों के तहत गंभीरता से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समक्ष रखा जाएगा, ताकि उनका समुचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

बैठक के दौरान पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। प्रतिनिधियों ने बताया कि कई मामलों में लंबे समय से निर्णय लंबित हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मंत्री ने सुझाव दिया कि पेंशन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए उपलब्ध संस्थागत तंत्रों का प्रभावी उपयोग किया जाए। एक अधिकारी के अनुसार, मंत्री ने विशेष रूप से पेंशन अदालत, सीपीएनजीआरएएम और अन्य पेंशन शिकायत मंचों का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि इन मंचों के माध्यम से शिकायतों का समाधान अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान मेल मोटर सर्विस से संबंधित मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के साथ–साथ बदलते संचार तंत्र में इसकी भविष्य की भूमिका पर भी चर्चा की। कर्मचारियों ने इस सेवा के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके।

इसके अलावा, कर्मचारियों ने मौजूदा योजनाओं के तहत करियर प्रगति के अवसरों पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव है, जिससे कई कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

बैठक में ग्रामीण डाक सेवकों से जुड़े मुद्दा. ˇ पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज, वेतन संरचना और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित समस्याओं को उठाया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक सेवकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका को भली–भांति समझती है और उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं मिल सकें।

अरविंद गुप्ता ने सीडीएफ से जैन स्थानक में लिफ्ट लगाने के लिए 34 लाख रूपये की सिफारिश की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वार्ड संख्या 32 जैन नगर जम्मू के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तहत एक अहम विकास कार्य की सिफारिश की है। पूर्व उपमहापौर धर्मवीर सिंह की उपस्थिति में अरविंद गुप्ता ने जैन सभा के प्रतिनिधियों को आत्म भवन जैन स्थानक में लिफ्ट लगाने के लिए आधिकारिक सिफारिश पत्र सौंपा।

प्रस्तावित परियोजना में सामुदायिक भवन में आठ यात्रियों की क्षमता वाली मशीन रूम लेस लिफ्ट की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और संचालन शामिल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों और आगंतुकों के लिए पहुंच को आसान बनाना है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 34 लाख रुपये रखी गई है। इसमें डीजी सेट की लागत शामिल नहीं है। अरविंद गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्ताव की जांच कर 45 दिनों के भीतर तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की जाएं।

अरविंद गुप्ता ने कहा कि यह पहल समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लिफ्ट की स्थापना से बुजुर्गों महिलाओं और दिव्यांगजनों को काफी सुविधा मिलेगी और उन्हें भवन तक पहुंचने में आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि समावेशी विकास हमारी प्राथमिकता है और इस प्रकार की परियोजनाएं जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य शुरू होने के बाद इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और प्रगति की नियमित जानकारी दी जाए। किसी भी प्रकार की देरी या कार्य की अनुपयुक्तता की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत कारण बताए जाएं। जैन सभा के सदस्यों ने इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया।

सेना ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला स्कूल हॉस्टल में फंसे 34 लोगों को बचाया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ने से मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में एक स्कूल के छात्रावास में फंसे 30 छात्रों और चार शिक्षकों सहित 34 लोगों को सेना ने बचाया। अधिकारियों ने बताया,

"लगातार और तेज बारिश के कारण रफीबाद (बारामूला) के वतरगाम इलाके में एक नाले में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे स्थानीय स्कूल के छात्रावास में बाढ़ आ गई। नतीजतन, 30 स्कूली बच्चे और चार शिक्षक परिसर के अंदर फंस गए और उनके पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था।" स्थानीय लोगों ने वहां तैनात सेना की टुकड़ी से संपर्क किया, जिसने तुरंत मानवीय सहायता अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया, "चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और खतरनाक रूप से ऊंचे जलस्तर के बावजूद, टीमें फंसे हुए लोगा. ` तक पहुंचने और सभी 34 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाब रहीं।"

बचाव कार्य के बाद, सेना ने बचाए गए बच्चों और कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल और जलपान सहित आवश्यक सहायता प्रदान की।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय युवाओं ने सेना की सहायता की।

बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर के तुलैल इलाके में हिमस्खलन की सूचना मिली है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि यह हिमस्खलन पहाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

पिछले 48 घंटों में घाटी के मैदानी इलाकों में मध्यम वर्षा और कुछ ऊंचे इलाकों में हिमपात हुआ।

बारामूला में पिछले 24 घंटों में 70 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो घाटी में सबसे अधिक है। हंदवारा क्षेत्र के नौगाम में इसी अवधि के दौरान 58.2 मिमी वर्षा हुई, इसके बाद काजीगुंड (48.6 मिमी) और कुलगाम (42.2 मिमी) का स्थान रहा। श्रीनगर शहर में भी अच्छी खासी बारिश हुई, जहां पिछले 24 घंटों में 31. 6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर में बुधवार को बादल छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद सप्ताहांत में एक बार फिर बारिश होगी।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जनता का भरोसा कम हो रहा है : फारूक

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है।

पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि इस संवैधानिक अधिकार का लंबे समय तक टलना ष्खेदजनक दुर्भाग्यपूर्ण है।

अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार द्वारा लंबे समय से आश्वासन दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है और इसे रोके रखने से लोगों की आकांक्षाएं अधूरी रह गई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की देरी से असंतोष की भावना बढ़ रही है और उन्होंने विश्वसनीय और जवाबदेह शासन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से नागरिकों के साथ संवाद जारी रखने, उनकी चिंताओं को उठाने और गरिमा, लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने का आग्रह किया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख को दोहराते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वकालत करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मार्च में जम्मू डिवीजन में 11,000 से अधिक बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया।

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में मार्च माह के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाला. ` के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत 11 हजार से अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान कुल मिलाकर लगभग 62 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है, जो रेलवे प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को जानक. ारी देते हुए बताया कि यह अभियान विशेष रूप से रेलवे सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की सख्ती से न केवल राजस्व में वृद्धि होती है, बल्कि यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कटड़ा, श्रीनगर और बडगाम सहित पंजाब के पठानकोट छावनी जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इन स्टेशनों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर टिकट जांच कर्मचारियों की तैनाती बढ़ाई गई थी, ताकि बिना टिकट यात्रा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि मार्च माह के दौरान नवरात्रि उत्सव के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। इस दौरान भीड़भाड़ को देखते हुए टिकट जांच कर्मचारियों ने विशेष सतर्कता बरती और लगातार निगरानी रखी। अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए बिना टिकट यात्रियों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया और रेलवे नियमों का पालन सुनिश्चित किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या जुर्माने का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मार्च का महीना रेलवे के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि इस दौरान यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि टिकट जांच कर्मचारियों ने चौबीसों घंटे मेहनत करते हुए यह सुनिश्चित किया कि ईमानदार यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान से प्राप्त राजस्व केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रेलवे नियमों के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे बिना टिकट यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना भी है। इस अभियान के माध्यम से रेलवे ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधा. जनक यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाएगा।

चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर विस्फोट, कोई हताहत नहीं

सबका जम्मू कश्मीर

चंडीगढ़ : पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय के बाहर अचानक एक विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन विस्फोट ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना सेक्टर 37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हुई, जहां शाम करीब पांच बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

मजबूरी क्या है? उमर ने फारूक अब्दुल्ला पर हमले के कुछ हफ्तों बाद राष्ट्रीय परिषद मुख्यालय से सुरक्षा हटाए जाने की कड़ी आलोचना की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) मुख्यालय से सुरक्षा हटाए जाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे ष्समझ से परेष् बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले के एक महीने से भी कम समय बाद उठाया गया है।

उमर अब्दुल्ला की यह टिप्पणी जम्मू और कश्मीर विधानसभा में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के साथ हुई आधे घंटे की तीखी बहस के बाद आई। राथर ने मांग की कि या तो जम्मू-कश्मीर को ष्जोखिम-मुक्तष् घोषित किया जाए या सभी को समान सुरक्षा प्रदान की जाए।

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रीनगर स्थित ष्नवाई सुबहष् परिसर से सुरक्षाकर्मियों को पूरी तरह हटाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह परिसर पार्टी का मुख्यालय है, जहां अक्सर तीन बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके दिग्गज राजनेता फारूक अब्दुल्ला आते-जाते रहते हैं।

उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता को हाल ही में मिले जानलेवा खतरे का हवाला देते हुए प्रशासनिक फैसले के चिंताजनक समय पर प्रकाश डाला। 11 मार्च को जम्मू में एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल गोली लगने से बच गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ष्नसी मुख्यालय की सुरक्षा कम नहीं की गई है, बल्कि पूरी तरह से हटा दी गई है।ष् "यह अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला पर हमले को अभी कुछ ही सप्ताह हुए हैं। उस समय सभी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यह चिंता का विषय है।"

उन्होंने मुख्यालय को असुरक्षित छोड़ने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, विशेष रूप से अपने पिता के बार-बार आने-जाने का जिक्र करते हुए।

"फारूक साहब सप्ताह में दो से तीन बार उस कार्यालय में जाते हैं। इसकी क्या मजबूरी है? सुरक्षा हटाने का क्या कारण है? अगर हमें प्रशासन से पता चल जाए तो अच्छा होगा," उन्होंने कहा।

सत्तारूढ़ दल के मुख्यालय से सुरक्षा हटाने के फैसले पर जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि सुरक्षा मनमाने ढंग से या राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए।

"जम्मू-कश्मीर में सभी दलों के नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों को ध्यान में रखते हुए, इसे निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सीएसआईआर-आईआईआईएम और जेकेईडीआई ने हाथ मिलाया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : सीएसआईआर–प्प्ड और इसके प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (प्प्ड–ज्ठप्) ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (श्रज्ञम्क्प्) के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसका उद्देश्य नवाचार, इनक्यूबेशन और अनुसंधान–आधारित विचारों के व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का लक्ष्य स्टार्टअप्स को उन्नत वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे, मेंटरशिप नेटवर्क और वित्तपोषण के अवसरों से जोड़ना है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में प्रौद्योगिकी–आधारित उद्यमों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार हो सके। जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (श्रज्ञम्क्प्) की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य सचिव और श्रज्ञम्क्प् के निद. शक खालिद जहांगीर अपनी टीम के साथ इस चर्चा में शामिल हुए, जबकि सीएसआईआर–प्प्ड जम्मू की ओर से सीएसआईआर–प्प्ड के निद. शक डॉ. जबीर अहमद प्प्ड ज्ठप् टीम के साथ उपस्थित थे और उन्होंने संस्थागत संपर्क के लिए विशेषज्ञता और तौर–तरीकों पर चर्चा की।

सीएसआईआर–प्प्ड के निदेशक डॉ. ज़बीर अहमद ने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस क्षेत्र की वैज्ञानिक और संसाधन क्षमता पर बल देते हुए कहा कि यही इसकी असली ताकत है। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में 1,500 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई अभी तक अनछुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि संस्थान कैप्टिव कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, कृषि प्रौद्योगिकी विकास, प्रसंस्करण और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स तथा प्री–क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान में संलग्न है।

उन्होंने कहा कि संस्थान जीएलपी–प्रमाणित प्रयोगशालाओं, फर्मेंटेशन पायलट प्लांट्स, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन, सीजीएमपी सुविधाओं, संस्थान और इसके नवाचार परिसरों में स्थित विश्लेषणात्मक सुविधाओं सहित अपने उन्नत बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करके स्टार्टअप्स को पूर्ण समर्थन देने के
लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान नवीन विचारों को प्रभावशाली, बाजार के लिए तैयार उत्पादों में परिवर्तित करने पर है। हम स्टार्टअप्स के लिए अपनी सुविधाएं खोल रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा, जैव प्रौद्योगिकी और सुगंधित पौधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों को 24×7 सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं।" उन्होंने जम्मू और कश्मीर के स्टार्टअप्स को मुंबई स्थित सीएसआईआर के इनोवेशन कॉम्प्लेक्स सहित राष्ट्रीय नवाचार केंद्रों से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा, ताकि उद्योग जगत से जुड़ाव बढ़े और बाजार तक पहुंच आसान हो सके। डॉ. अहमद ने उभरते स्टार्टअप्स को संपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए मजबूत संस्थागत संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए, उद्योग एवं वाणिज्य सचिव और जम्मू–कश्मीर प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जेकेईडीआई) के निदेशक खालिद जहांगीर ने स्टार्टअप्स को अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रोटोटाइपिंग सुविधाओं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूत संस्थागत साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में लगभग 1,400 स्टार्टअप हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों, जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण की ओर रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप नीति के तहत, सरकार ने चयनित स्टार्टअप्स को पहले ही ध्1.25 करोड़ से अधिक की सीड फंडिंग वितरित कर दी है, जबकि कई अन्य प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया बेहद सख्त है, जिसमें शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों द्वारा कई चरणों में मूल्यांकन किया जाता है। जेकेईडीआई में सीआईआईबीएम के प्रभारी इरतीफ लोन ने स्टार्टअप नीति का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि इस नीति का उद्देश्य 2027 तक जम्मू और कश्मीर को एक अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थापित करना है।

भजन गायक अमर पंजाबी का नया भजन मां दे मंदिर ते जल्द होगा रिलीज, श्रद्धालुओं से सुनने की अपील

राम सिंह

पंजाब के प्रसिद्ध भजन गायक अमर पंजाबी के लोकप्रिय भजन सोहनी लगदी बारात शिव दी की अपार सफलता के बाद अब एक और नया भजन ष्मां दे मंदिर तेष् जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। इस भजन को भी अमर पंजाबी ने अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत किया है।

भजन के बोल अमरनाथ कुंडल द्वारा लिखे गए हैं, जबकि इसका संगीत जतिन बिट्स (गुरदासपुर) ने तैयार किया है। वीडियो का निर्देशन एसआर अतरी ने किया है, जिसे बेहद सुंदर तरीके से फिल्माया गया है।

यह भजन जय बालाजी कंपनी के बैनर तले प्रस्तुत किया जा रहा है। गायक और पूरी टीम ने सभी प्रभु प्रेमियों से अपील की है कि वे इस भजन को सुनें और अपना प्यार व आशीर्वाद दें।

युवाओं में बढ़ता नशा बना गंभीर चिंता का विषय, एडवोकेट सुशील गुप्ता ने जताई चिंता

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : गुरुवार को कठुआ में हुआ घटनाक्रम को लेकर एडवोकेट सुशील गुप्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का बढ़ता उपयोग एक बड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब, तंबाकू, गांजा, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव, तनाव या गलत संगत के कारण होती है, लेकिन धीरे–धीरे यह लत बन जाती है।

उन्होंने बताया कि नशे के कारण युवाओं की पढ़ाई और करियर प्रभावित होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और परिवार व समाज में रिश्ते भी खराब होते हैं।

कई बार यह अपराध, सड़क हादसों और मानसिक बीमारियों का कारण भी बनता है।

एडवोकेट सुशील गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से बचने के लिए युवाओं को जागरूक होना जरूरी है। खेल–कूद, योग और सकारात्मक माहौल अपनाकर नशे से दूर रहा जा सकता है। साथ ही माता–पिता और शिक्षकों को भी बच्चों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सभी को मिलकर इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए।

सामूहिक प्रयासों से जम्मू-कश्मीर विधानसभा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया जा सकता है : महबूबा मुफ्ती

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू, मार्च : पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा की शक्ति और गरिमा को बहाल करने के लिए सरकार और विपक्ष से एकजुट प्रयासों का आह्वान किया।

मुफ्ती ने यह टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर गैलरी से देखने के बाद की। 2018 में भाजपा समर्थित सरकार गिरने के बाद सदन में यह उनकी पहली उपस्थिति थी।

पीडीपी अध्यक्ष प्रश्नकाल के दौरान कुछ समय तक उपस्थित रहीं। उनके चार पार्टी विधायक भी उपस्थित थे, जिनमें से एक, रफीक अहमद नाइक ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन से संबंधित एक प्रश्न के ष्संतोषजनक और विस्तृतष् उत्तर के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा की।

"आज मैंने विधानसभा का दौरा किया और मुझे अच्छा लगा। इससे मुझे विशेष रूप से अपने पिता (मुफ्ती मोहम्मद सईद) की याद आ गई३ हमारी विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि, 2019 के बाद से किसी न किसी रूप में इसका महत्व और अधिकार कम हो गया है," मुफ्ती ने कहा, उस वर्ष का जिक्र करते हुए जब केंद्र ने जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।

संस्था के धीरे–धीरे पुनर्निर्माण के प्रयासों में अपनी पार्टी के समर्थन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "पीडीपी निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी (एनसी) की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है३ मुझे दृढ़ विश्वास है कि सरकार और विपक्ष दोनों के सामूहिक प्रयासों से जम्मू–कश्मीर विधानसभा की खोई हुई शक्ति को बहाल किया जा सकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि पीडीपी ने सदन में कई विधेयक पेश किए हैं जिनके लिए राज्य का दर्जा देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्हें "मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश ढांचे के भीतर" पारित किया जा सकता है। उन्होंने नए मंडलों और जिलों के गठन और कई वर्षों से छोटे–छोटे जमीनों पर रह रहे गरीब लोगों को स्वामित्व अधिकार देने जैसे विधेयकों का जिक्र किया।

पीडीपी अध्यक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने वादों को पूरा करे, खासकर रोजगार, आरक्षण और नियमितीकरण के संबंध में। उन्होंने कहा,

"हमारे कार्यकाल में हमने दिहाड़ी मजदूरा. के मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाया था। सरकार को उस समय लागू किए गए ढांचे की समीक्षा और अध्ययन करना चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों की हालत बेहद खराब है३वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं।" उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को मानवीय मुद्दा माना जाए, न कि राजनीतिक।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026–27 के लिए सभी आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं।

लघु एवं मध्यम करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्ज्त फॉर्म 1–4 30 मार्च को अधिसूचित किए गए थे, जबकि प्ज्त फॉर्म 2, 3, 5, 6 और 7, साथ ही **ITR&U** (अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए) मंगलवार को अधिसूचित किए गए। प्ज्त (आयकर रिटर्न) अधिसूचना के साथ, व्यक्ति, व्यवसाय और अन्य संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2025–26 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।

व्यक्तियों और उन लोगों के लिए जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, प्ज्त दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में कृषि परिवर्तन के लिए एसकेयूएएसटी-जम्मू और आईएफपीआरआई के सहयोग पर चर्चा करने के लिए एलजी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक जम्मू में आयोजित की गई, जिसमें शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के बीच प्रस्तावित रणनीतिक सहयोग पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने इस प्रस्तावित साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि आईएफपीआरआई की वैश्विक विशेषज्ञता और शोध अनुभव जम्मू–कश्मीर में कृषि नीति निर्माण को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बदलते समय में कृषि क्षेत्र को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए डेटा–आधारित निर्णय और सुदृढ़ संस्थागत ढांचा अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में एसकेयूएएसटी–जम्मू और आईएफपीआरआई के सहयोग से एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विशेष रूप से चर्चा की गई। यह केंद्र खाद्य नीति और डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में कार्य करेगा और इसे एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इस केंद्र का उद्देश्य कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं की निरंतर निगरानी करना, नीतियों का मूल्यांकन करना

और सटीक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना होगा।

उपराज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार का केंद्र न केवल जम्मू–कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्वतीय और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में कृषि की विशेष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जाना चाहिए। उच्च मूल्य वाली फसलों और उत्पाद प्रणालियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

बैठक में आईएफपीआरआई के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। आईएफपीआरआई–दक्षिण एशिया के निदेशक डॉ. शाहिदुर राशिद और वरिष्ठ शोध अध्येता डॉ. अंजनी कुमार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी उपायों पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों और सटीक आंकड़ों के उपयोग से कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाया जा सकता है।

बैठक के दौरान डॉ. अंजनी कुमार ने जम्मू–कश्मीर में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यदि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और नीतियों को ठोस आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाए, तो यह क्षेत्र तेजी से प्रगति कर सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को नई तकनीकों और बाजार से जोड़ने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

विचार–विमर्श के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि विभिन्न सरकारी पहलों के बीच समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, जम्मू–कश्मीर प्रतिस्पर्धी कृषि परियोजना और मिशन युवा जैसी पहलों को आपस में जोड़कर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है।

उपराज्यपाल ने कहा कि लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं को कृषि विकास की मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समावेशी विकास के बिना कृषि क्षेत्र में स्थायी प्रगति संभव नहीं है। इसके लिए ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखें और उन्हें समान अवसर प्रदान करें।

राजौरी में हेड कांस्टेबल 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी का बड़ा एक्शन

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू/राजौरी द्य अनिल भारद्वाज

जम्मू–कश्मीर के राजौरी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान थाना थन्नामंडी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मी उनके वाहन को छोड़ने के बदले पैसे की मांग कर रहा था। यह वाहन शाहदरा शरीफ जाते समय एक सड़क हादसे में शामिल हुआ था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पहले ही 5 हजार रुपये दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी द्वारा और 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। साथ ही धमकी दी गई थी कि पैसे न देने पर केस को लंबा खींचा जाएगा और वाहन रिलीज नहीं किया जाएगा।

परेशान होकर शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि ली, उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Helpline

पुलिस स्टेशन	
बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन	
बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रसोई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मददन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

एनएच -44 पर आधी रात कार्रवाई : वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जम्मू–कश्मीर के कठुआ जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे–44 पर एक ट्रक को जब्त किया है।

यह कार्रवाई तड़के करीब 2रू30 बजे चढ़वाल क्षेत्र में की गई।

अधिकारियों के अनुसार, ट्रक (श्रज्ञ08ष्–9212) में बी.एल. प्रजाति की लकड़ी और जलाऊ लकड़ी अवैध रूप से ले जाई जा रही थी।

जांच में पाया गया कि यह परिवहन नियमों के खिलाफ था और रात के समय वन उत्पादों के परिवहन पर लगे प्रतिबंध का भी उल्लंघन किया गया।

इस ऑपरेशन का नेतृत्व ब्लॉक ऑफिसर गंदीप सिंह ने किया। उनके साथ वन विभाग की टीम के सदस्य कमल कुमार, संजय कुमार, नरेश कुमार, राजिंदर कुमार और पंकज शर्मा मौजूद थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत जब्त कर लिया।

कार्रवाई की निगरानी रेंज ऑफिसर अनुशा कोल्ली आईएफएस और मुनीश गुप्ता ने की, जबकि पूरे ऑपरेशन पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) कठुआ अंकित सिन्हा (आईएफएस) की नजर रही।

जब्त ट्रक, लकड़ी और चालक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरिया चक नर्सरी में सुरक्षित रखा गया है।

वन विभाग ने साफ किया है कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राशन कार्ड विभाजन और नए डिपो खोलने का जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया ने उठाया मुद्दा

सबका जम्मू कश्मीर

जसरोटा/कठुआ। जम्मू–कश्मीर विधानसभा में जनहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए विधायक राजीव जसरोटिया ने अपने क्षेत्र में राशन कार्ड विभाजन (बिफरकेशन) और नए राशन डिपो खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी और अलग हो रहे परिवारों के कारण पुराने राशन कार्डों का विभाजन जरूरी हो गया है, ताकि सभी पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल सके।

उन्होंने सरकार से मांग की कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जरूरत वाले इलाकों में नए राशन डिपो भी खोले जाएं। इससे लोगों को राशन लेने में सुविधा होगी और लंबी दूरी तय करने की समस्या से राहत मिलेगी। सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संविधान में प्रेस को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाना चाहिए : फुटेला

सबका जम्मू कश्मीर

रुद्रपुर। गोवा में आयोजित श्सीनियर जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान, पत्रकारों की सुरक्षा, पेंशन और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विचार–विमर्श किया गया। देश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने सर्वसम्मति से मांग की कि पत्रकार समुदाय के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीतिगत उपाय अपनाए जाएं।

सभा को संबोधित करते हुए, श्नेशनल जर्नलिस्ट्स फेडरेशनश के प्रदेश अध्यक्ष और एक अनुभवी पत्रकार प्रदीप फुटेला ने कहा कि यद्यपि प्रेस को व्यापक रूप से लोकतंत्र का श्चौथा स्तंभश माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसे औपचारिक रूप से यह संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)() अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो प्रदान करता है, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विशिष्ट अधिकारों के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभी भी अभाव है।

फुटेला ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार समाज और लोकतंत्र, दोनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि पूरे देश में एक प्रभावी श्पत्रकार सुरक्षा कानूनश बनाना अनिवार्य है, ताकि पत्रकार बिना किसी भय के अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन का मुद्दा उठाते हुए, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में दी जाने वाली मासिक पेंशन मात्र घ8,000 हैकृएक ऐसी राशि जिसे उन्होंने आज की आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए अत्यंत अपर्याप्त बताया। उन्होंने मांग की कि इस मासिक पेंशन को बढ़ाकर घ25,000 किया जाए और पेंशन पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर घ6 लाख किया जाए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधाओं के प्रावधान; लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी; ब्याज–मुक्त आवास ऋण की व्यवस्था; और रद्द की गई प्रेस मान्यता (बबतमकपजं. जपवद) को बहाल करने की मांगें भी रखीं। साथ ही, रेल यात्रा पर मिलने वाली 50 प्रतिशत की रियायत को बहाल करने का मुद्दा भी उठाया गयाकृयह एक ऐसा लाभ था जो पहले पत्रकारों को उपलब्ध था।

बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा और पत्रकार बिरादरी के हितों की रक्षा के लिए वास्तव में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

13 अप्रैल : खालसा सृजन दिवस

बलविंदर बालम,

भारत देश में बैसाखी का पवित्र त्योहार धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह त्योहार अप्रैल माह के मध्य में आता है। भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहां–जहां भारतीय रहते हैं, वहां इसे मेले के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर इस त्योहार को मनाते हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। बैसाखी का त्योहार किसान जमींदार ढोल–ढमक्कों, भांगड़े और गिद्धे के साथ, रिश्तों की मिठास में मनाते हैं। इस समय फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। सोने सी चमकती गेहूं की फसल अपने यौवन की दास्तां कहती हुई किसान को मालामाल करती है। फसलें हंसती हुई झूमती हैं और उन्नति का संद.श देती हैं। फूल अपनी सुगंध से वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। आम के वृक्षों पर बौर खुशहाली का संकेत देते हैं। लहलहाते खेतों में पीली सरसों दुल्हन सी सुन्दर लगती है। चारों ओर बहार ही बहार होती है, मानो पतझड़ मुंह छिपाकर भाग गया हो।

बैसाखी वाले दिन खुशियां आसमान छूती हैं। घरों में तरह–तरह के मिष्ठान एवं व्यंजन बनते हैं। मेहमानों की आमद रिश्तों में शहद सी मिठास घोल देती है।

प्राचीन इतिहास गवाही देता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अमृत प्राप्त हुआ, जिसे पीने वाला अमर हो जाता था। यह कथा अमरत्व और धर्म की विजय का प्रतीक है।

श्री गुरु नानक देव जी तथा अन्य सभी गुरुओं ने ष्सतनामष् का अमृत बांटा और मानवता को सच्चाई एवं समानता का मार्ग दिखाया।

आज का दिन सिख इतिहास में अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के पावन अवसर पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंच प्यारों को अमृत छका कर खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अलग–अलग जाति, धर्म और क्षेत्रों से आए पांच श्रद्धालुओं को सिंह की उपाधि देकर खालसा कृ अकाल पुरुख की फौज कृ का निर्माण किया।

ये पांच प्यारे थे : भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी और भाई मोहकम सिंह जी। गुरु जी ने दस्तार, केश और पंच ककारों की परंपरा स्थापित की तथा एक निर्भीक, सच्चे और शुद्ध खालसा की सृजना की। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उनके पिता, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी यह ज्योति सदैव सूर्य की भांति चमकती रहेगी। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग, अमृतसर में अंग्रेजी शासन के दौरान जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें अनेक लोग शहीद हुए। यह दिन अन्याय के खिलाफ संघर्ष की याद दिलाता है।

दमदमा साहिब, तलवंडी साबो में बैसाखी का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लाखों लोग अमृत पान कर इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। बैसाखी गंगा–सागर (बंगाल) में भी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास बनीखेत स्थित श्री भूरी नाग देवता मंदिर में भी श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश को शुभ माना जाता है। यह समय प्रकृति के सौंदर्य और आनंद का प्रतीक होता है। बैसाखी का त्योहार सिखों के पवित्र स्थल श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। देश–विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और गुरुओं की वाणी का अमृत ग्रहण कर सुख, शांति और आनंद प्राप्त करते हैं।

प्रसिद्ध कवि धनी राम चत्रिक की पंक्तियाँ हैं :

कणकां दी मुक गई राखी, ओ जट्टा आई बैसाखी।

बलविंदर बालम, गुरदासपुर

ओंकार, गुरदासपुर (पंजाब)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ में पंचायत वोटर लिस्ट के लिए विशेष कैंपों का निरीक्षण, सभी पात्र लोगों के नाम जोड़ने के निर्देश

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) कठुआ राजेश शर्मा ने पंचायत मतदाता सूची के संशोधन के लिए लगाए गए विशेष कैंपों का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी मिडिल स्कूल चंगरान और सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल बडाला का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कैंपों में चल रही नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया की जांच की और कर्मचारियों से बात कर काम को सही तरीके से करने के निर्देश दिए।

डीईओ ने कहा कि पंचायत की वोटर लिस्ट, विधानसभा की लिस्ट से अलग होती है। इसलिए सभी पात्र लोग अपने नाम जरूर चेक करें और सूची में शामिल करवाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और सभी का नाम सूची में जोड़ा जाए।

राजेश शर्मा ने बताया कि पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को फोटो पहचान पत्र भी दिया जाएगा। पात्रता की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 रखी गई है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन कैंपों में आकर अपना नाम जुड़वाएं। साथ ही घर–घर जाकर भी जांच और नाम जोड़ने का काम किया जाएगा।

कैंप में आने वाले लोगों से कहा गया है कि वे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि काम आसानी से हो सके।

कठुआ बनता नशे का अड्डा : युवाओं का भविष्य खतरे में

राज कुमार

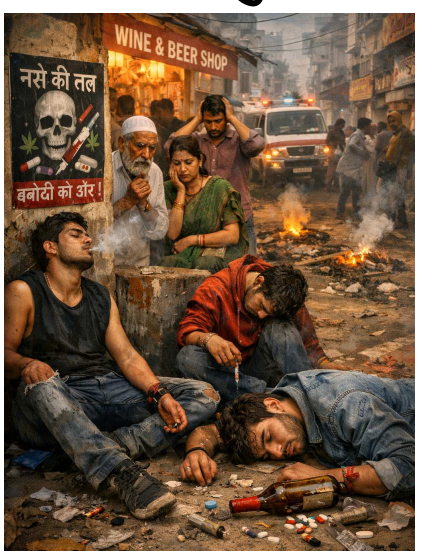

कठुआ : एक समय था जब नशे की चर्चा मुख्य रूप से पंजाब या अन्य राज्यों तक सीमित रहती थी। पंजाब में "चिट्टा" (हेरोइन) के बढ़ते प्रचलन ने वहां के युवाओं की हालत बेहद चिंताजनक बना दी थी। इस गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने के लिए फिल्म उद्योग ने भी भूमिका निभाई और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को उजागर किया गया। हालांकि सरकारों ने समय–समय पर कार्रवाई की, लेकिन नशे के बड़े नेटवर्क और तस्करों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई।

पंजाब का पड़ोसी होने के कारण अब जम्मू–कश्मीर, विशेषकर जिला कठुआ, भी इस नशे की चपेट में तेजी से आ रहा है। कठुआ, जिसे जम्मू–कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पंजाब से सटा होने के कारण नशे के कारोबार के लिए संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। लखनपुर जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है, जहां से राज्य में प्रवेश करने वाले रास्तों के साथ–साथ अवैध गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

पिछले कुछ समय में कठुआ जिले में युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने और अपनी जान गंवाने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े कितने सही हैं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं और कई युवा अभी भी इस दलदल में फंसे हुए हैं।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों–बीच स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के पीछे खुले में पड़े इंजेक्शन जैसे दृश्य सामने आए हैं। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह उठता है कि इन इंजेक्शनों का उपयोग कौन कर रहा था और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या यह नशे की लत में डूबे युवाओं का अड्डा बन चुका है, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने कहा कि पिछले एक वर्ष में 100 से अधिक युवाओं की मौत नशे के कारण हुई है। यह आंकड़ा न केवल डराने वाला है, बल्कि यह बताता है कि समस्या कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। उन्होंने ड्रग डि–एडिक्शन सेंटरों की कमी को लेकर भी सवाल उठाए, जो इस बात का संकेत है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में बुनियादी ढांचे की भी कमी है।

हालांकि पुलिस विभाग समय–समय पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करता है और कई मामलों में सफलता भी मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास पर्याप्त हैं? समाचार पत्रों में अक्सर पुलिस की उपलब्धियों की खबरें आती हैं, जो सराहनीय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नशे की बढ़ती घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केवल छोटी मछलियों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बड़े तस्करों और नेटवर्क को तोड़ना होगा।

इस समस्या का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा संस्थान और समाज सभी की भागीदारी हो। सबसे पहले, नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को सही उपचार मिल सके। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है।

इसके अलावा, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। परिवारों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा और उनके व्यवहार में हो रहे बदलावों को समय रहते पहचानना होगा। यदि किसी युवा में नशे की लत के संकेत दिखाई दें, तो उसे छिपाने के बजाय मदद लेने की पहल करनी चाहिए। अंततः, यह समझना होगा कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि समय रहते कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। कठुआ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस विनाशकारी रास्ते से बचाया जा सके। नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तभी हम अपने युवाओं को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे।

कठुआ पुलिस ने स्थानांतरित अधिकारियों को दी विदाई

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जम्मू–कश्मीर पुलिस कठुआ ने जिले से स्थानांतरित हो रहे अधिकारियों के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान एसपी ऑप्स बॉर्डर कंडी मुकुंद तिबरेवाल, अतिरिक्त एसपी राहुल चरक, एसपी ऑप्स अपर बिलावर आउमर इकबाल, सीनियर पीओ मुनीश कुमार और पीओ बंधना शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश शर्मा और एसएसपी मोहिता शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिक. ारी मौजूद रहे।

एसएसपी मोहिता शर्मा ने अधिकारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून–व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

समारोह में अन्य अधिकारियों ने भी उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अंत में स्थानांतरित अधिकारियों ने सभी का धन्यवाद किया।

'सक्ती जिले में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जिला उपाध्यक्ष प्रकाश कमल ने दिया इस्तीफा'

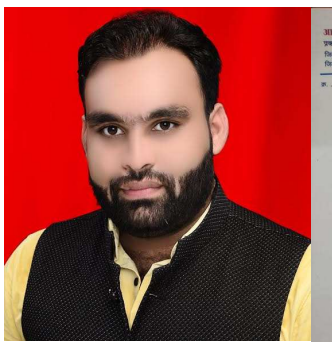

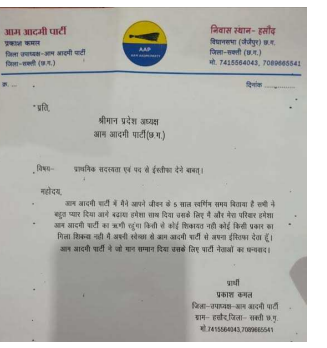

सबका जम्मू कश्मीर

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में आम आदमी पार्टी (।।च) को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश कमल ने अपने पद सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले से स्थानीय राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है और इसे लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

प्रकाश कमल ने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि वे निजी कारणों के चलते पार्टी के सभी दायित्वों से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया और क्षेत्र में उन्हें जो भी सम्मान मिला, वह पार्टी की ही देन है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी के साथ काम करते हुए उन्हें संगठनात्मक अनुभव प्राप्त हुआ और जनसेवा का अवसर मिला, जिसके लिए वे सदैव आभारी रहेंगे।

हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे के निजी कारणों का विस्तार से खुलासा नहीं किया, जिससे उनके इस कदम को लेकर अटकलों का दौर जारी है।

प्रकाश कमल सक्ती जिले में आम आदमी पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे। संगठन को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों को उठाने और जनसंपर्क बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी दर्ज कराई थी।

उनके अचानक इस्तीफे से पार्टी कार्यकर्ताओं में आश्चर्य और निराशा का माहौल है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा आने वाले समय में जिले की राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

फिलहाल पार्टी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार संगठन स्तर पर स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है और क्या प्रकाश कमल भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की ओर रुख करते हैं।

जम्मू–कश्मीर में राशन कार्ड न बनने से लोग परेशान, सरकार से जल्द समाधान की मांग

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ। जम्मू–कश्मीर में लंबे समय से राशन कार्ड न बनने की समस्या को लेकर आम लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर मदीना क्षेत्र के निवासी गणेश दत्त ने सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

गणेश दत्त का कहना है कि समय रहते राशन कार्ड बनना जरूरी है, ताकि लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि कई परिवार अब अलग–अलग हो चुके हैंकृबच्चे अपने परिवार के साथ अलग रह रहे हैं, जबकि माता–पिता अलग रह रहे हैं। ऐसे में नए राशन कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है।

वहीं गणेश दत्त ने भी बताया कि राशन कार्ड न बनने के कारण वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री और जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि राशन कार्ड से जुड़ी वेबसाइट और प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, ताकि नए परिवारों के नाम जोड़ने और जरूरी कागजात बनवाने में आ रही दिक्कतों का समाधान हो सके।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, शनिवार, अप्रैल 4, 2026

हीरानगर में पंचायत मतदाता सूची संशोधन का निरीक्षण, एसडीएम ने जनभागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर : एसडीएम हीरानगर फुलेल सिंह ने पंचायत मतदाता सूची संशोधन कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए विभिन्न पंचायत मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चक भगवाना और चक गोपाला सहित कई केंद्रों का निरीक्षण किया।

दौरे के दौरान एसडीएम ने बूथ लेवल अधिक. ारियों और पंचायत चुनाव बूथ अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। ये अधिकारी लोगों को अपने वोटर कार्ड की जानकारी अपडेट और सही कराने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने मौके पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जागरूकता और सुविधाओं का भी आकलन किया। यह निरीक्षण जिला पंचायत चुनाव अधिकारी कठुआ के निर्देशों और राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए और सभी पात्र मतदाताओं को पूरा सहयोग दिया जाए। उन्होंने रिकॉर्ड सही रखने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित शिविरों में पहुंचकर अपने मतदाता विवरण की जांच और अपडेट जरूर करवाएं।

नाका चेकिंग में राजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गो-तस्करी की कोशिश नाकाम

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू/राजौरी द्य अनिल भारद्वाज

राजौरी पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान सतर्कता दिखाते हुए गो–तस्करी की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक वाहन को जब्त किया है। खालसा चौक पर नियमित जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक टाटा मोबाइल वाहन (श्रज्ञ11भ्–8171) को रोका, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति चला रहा था। तलाशी के दौरान वाहन में 5 मवेशी पाए गए, जिन्हें बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस मामले में थाना राजौरी में थ्प् नंबर 149/2026 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

NOTICE

I, Sandesh Rani, Wife of Darbar Singh, Resident of Ward No. 05, Taraf Bala, Tehsil Nagri Parole, District Kathua, UT of Jammu & Kashmir, do hereby declare that my name has been wrongly recorded as "Sandesh Devi" in my Aadhaar Card. That my correct and true name is "Sandesh Rani" as per my other official documents and records. I hereby request all concerned authorities and the general public to take note of the correction of my name from "Sandesh Devi" to "Sandesh Rani" for all official purposes. Any person having any objection to this change may contact the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice.

Deponent
(Sandesh Rani)
Date: 02/04/2026
Place: Nagri, Kathua

लचछीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का विसर्जन के साथ कथा का हुआ समापन

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन, लच्छीपूर : तहसील मढ़ीन के साथ लगते गांव लच्छीपूर में पिछले एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को विधिवत समापन हुआ। कथा के दौरान कथावाचक शास्त्री साईं दास ने अपने प्रवचना. ें से श्रद्धालुओं को भाव–विभोर कर दिया।

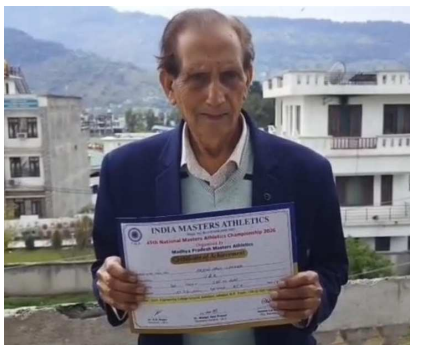

शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों के बीच भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।

प्रवचन के दौरान शास्त्री जी ने कहा कि मनुष्य को ईश्वर का नाम सिमरन करना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का रसपान करें और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर टिका है।

कथा के अंतिम दिन विसर्जन के दौरान शास्त्री जी ने गौ माता के संरक्षण पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि गाय हमारी पूजनीय माता है, जिसे सड़कों पर बेसहारा छोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने नेताओं और सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि गौ माता सुरक्षित नहीं है तो भविष्य चिंता का विषय है। इस मौके पर समाजसेवक ध्रुव सिंह, रिंपी शर्मा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

85 वर्षीय एथलीट प्रेम प्रकाश लूथरा ने जीते दो गोल्ड, पुंछ और जम्मू-कश्मीर का नाम किया रोशन

सबका जम्मू कश्मीर

पुंछ : जम्मू–कश्मीर सीमावर्ती जिला पुंछ के 85 वर्षीय बुजुर्ग एथलीट प्रेम प्रकाश लूथरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दो गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चौंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया और दोनों प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल किया।

उनकी इस बड़ी उपलब्धि से न केवल पुंछ जिले बल्कि पूरे जम्मू–कश्मीर में खुशी की लहर है।

इस उपलब्धि के सम्मान में श्री गीता भवन पुंछ में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग, समाजसेवी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान प्रेम प्रकाश लूथरा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

समारोह में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों की ओर ध्यान देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो, तो उम्र कभी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर में सभी 6 ट्यूबवेल साइटों पर पंपिंग मशीनें स्थापित, किसानों को मिलेगा लाभ : जावेद राणा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : सरकार ने जानकारी दी है कि हीरानगर विधानसभा क्षेत्र के सभी छह ट्यूबवेल स्थलों पर पंपिंग मशीनरी स्थापित कर दी गई है। इससे क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

यह जानकारी जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सदन में एक प्रश्न के जवाब में दी। यह सवाल विधायक विजय कुमार की ओर से विधायक राजीव जसरोतिया ने उठाया था। मंत्री ने बताया कि करोल–मथारियन, स्पलवान और बोबिया गांवों में नहरों, पंप कक्षों और पानी के टैंकों सहित सिंचाई से जुड़ा काम पूरा हो चुका है और अब यह चालू भी है।

हालांकि, कडियाला और चक चंगा जैसे क्षेत्रों में जमीन से जुड़े विवाद और अन्य समस्याओं के कारण अभी काम शुरू नहीं हो पाया है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही जमीन के मुद्दे सुलझेंगे और फंड उपलब्ध होगा, बाकी काम भी शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि योजना का पूरा फायदा किसानों तक पहुंच सके।

डीसी राजौरी की पहल से 11 साल की बच्ची को फिर मिली सुनने की शक्ति, भावुक कर देने वाली कहानी

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू/राजौरी : अनिल भारद्वाज

राजौरी जिले से एक दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक 11 साल की बच्ची को फिर से सुनने की शक्ति मिल गई। यह संभव हुआ डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा के समय पर किए गए प्रयासों से।

जानकारी के अनुसार, बच्ची जन्म से ही सुनने में असमर्थ थी। कुछ साल पहले उसका कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन हुआ था, जिससे वह सुनने और बोलने में सक्षम हो गई थी। लेकिन पिछले साल अचानक उसका डिवाइस खराब हो गया, जिससे वह फिर से सुनने से वंचित हो गई।

बच्ची के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और मां घरों में काम करती हैं, ऐसे में महंगे डिवाइस को ठीक कराना उनके लिए संभव नहीं था। जब यह मामला प्रशासन के पास पहुंचा, तो डीसी राजौरी ने तुरंत मदद के लिए कदम उठाए।

प्रॉमिस बैंक और सोशल वेलफेयर विभाग के सहयोग से बच्ची के डिवाइस को ठीक कराया गया। डिवाइस के दोबारा चालू होते ही बच्ची और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

इस भावुक पल में बच्ची ने डीसी ऑफिस जाकर अभिषेक शर्मा का धन्यवाद किया। इस दौरान डीसी ने बच्ची को अपनी कुर्सी पर बैठाकर उसका हौसला बढ़ाया, जो एक प्रेरणादायक दृश्य बना।

बच्ची ने जिला सोशल वेलफेयर अधिकारी अब्दुल रहीम और अन्य सभी लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने उसकी मदद की।

खेम राज मेहरा
ओबीसी मंडल प्रधान भाजपा, मढ़ीन

कुलदीप कुमार
भाजपा कठुआ (कोरे पुन्नु)
कठुआ (जम्मू-कश्मीर)

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार